

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 27 □ अंक - 345 □ रावपुर, बुधवार 8 जनवरी 2025 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया □ रावपुर □ बिलासपुर □ जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/78

जजों को वेतन देने में परेशानी और मुफ्त की रेवडियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, 8 जनवरी (न्यूज चैनल)। फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवडियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस गर्व की बेंच ने राज्य सरकारों पर टिप्पणी की है। चुनावी वार्डों के लिए सरकारों के पास पैसा है लेकिन जजों को सैलरी देने में परेशानी हो रही है। फ्री बीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मुफ्त की योजनाओं की बहाल आई हुई है और दिल्ली चुनाव में भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी ओर से अपने अपने बार्ड और जेजे किए हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काफी मानने रखती है और जजों को सैलरी देने में परेशानी की बात कही गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले चार सप्ताह से भी आम आदमी पार्टी विजली-पानी मुफ्त की बात



लगातार कही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के वेतन में परेशानी आ रही है। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गर्व और न्यायमूर्ति ऑमट्टी ने जजों मनीष को पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब अटॉर्नी जनरल अरुण कुमार ने दलील दी कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा निवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। राज्य के पास उन लोगों के

लिए पैसा है जो कोई काम नहीं करते। चुनाव आते हैं, आप लाइली बहाना और अन्य नयी योजनाएं घोषित करते हैं, जिसके तहत आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में अब आप दिन को न कोई पार्टी घोषणा कर रही है कि वे सप्ता में आने पर 2,500 रुपये देंगे। शीर्ष अदालत ने सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों को पेंशन के संबंध में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस गर्व ने कहा कि वित्तीय बोज़ की वास्तविक वित्तों की ब्याज में रखा जाना चाहिए। मुफ्त की रेवडी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें पीछे नहीं रहती है। अलग अलग प्रदेश में राज्य सरकारों की ओर से इसको लेकर ऐलान किया गया। मुफ्त में चीजें बांटने का इसका फायदा निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को भी हुआ है।

मालदीव के रक्षा मंत्री संग राजनाथ सिंह ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

नई दिल्ली, 8 जनवरी (न्यूज चैनल)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद हासन मीमून के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद हासन मीमून को मार्काश्री सेंटर में गाई ऑफ आनर दिया गया। उन्होंने माले की विकास परियोजनाओं और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में भारत के बिना शर्त समर्थन को दोहराया। विशेष रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए मीमून बुधवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।



मालदीव के अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में सिंह ने मीमून के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया जब मालदीव के राष्ट्रीय मोहम्मद मुस्जिद नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर थे। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ रक्षा उपकरणों और भंडारों की आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास, कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में अपनी को क्षमता निर्माण के रास्ते पेश कर रहा है।

राज्य ओपन स्कूल की उप सचिव को हाईकोर्ट से मिली राहत प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर, 8 जनवरी (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेक्रेट्री को प्रतिनियुक्ति नियम विरुद्ध तरीके से समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही सचिव को आदेश दिया है कि ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर कार्यभार ग्रहण कराना जाए।



सचिव को दिया आदेश

नवनीता सिंह शिक्षा विभाग की अक्सर हैं। उनकी पोस्टिंग पहले प्रभारी प्राचार्य डाक्टर के रावपुर पर हुई थी। 13 मार्च 2024 को राज्य शासन ने उन्हें ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर प्रतिनियुक्ति दी। आरोप है कि इस दौरान ओपन स्कूल की सचिव पुष्पा साहू उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से काम करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर उन्होंने मना किया, तो नवंबर 2024 में उन्होंने डिप्टी सेक्रेट्री को दिए गए प्रभार छीन लिया गया। इसके बाद उन्हें शोकांत नोटिस जारी किया गया। इसी दौरान सचिव ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने खुल्ल शिफा विभाग को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा। लेकिन, विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम

प्रतिनियुक्ति दी है। लेकिन, राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को दुरुपयोग कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश जारी किया है और उन्हें एक एक तरफा कार्यभार भी कर दिया है। इस मामले को सुनवाई जस्टिस एफ प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई, उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्यभार करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आरटीपीसीआर टेस्ट शुरू, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर होगी नजर

नई दिल्ली, 8 जनवरी (न्यूज चैनल)। हृदयम मेडन्युमो वायरस (एचएमएनवी) के देश में मामले सामने आने के बाद दिल्लीकर प्रदेश में सर्कटा बंद दी गई है। सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य वायरस है, जिससे घबराहना नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन होने में पहले भी लक्षण नहीं होते थे। साथ ही विशेष लेब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे।

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को इन्फ्यूएन्जा और गंधीर तीव्र क्षयन के संबंधित रोगियों की निगरानी रखने को कहा है। बाहरी

राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करने को कहा है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह एक सामान्य वायरस है, जिससे घबराहना नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन होने में पहले भी लक्षण नहीं होते थे। साथ ही विशेष लेब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे।

विरुद्ध तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए 13 दिवसों की डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह की एक तरफा कार्यभार कर दिया, जिस पर नवनीता सिंह ने उन्हें प्रतिनियुक्ति वापस लेने के लिए अपवाहन भी दिया और पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया, जिस अमान्य होकर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने अपने एक्जोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि उनका मूल पद स्कूल शिक्षा विभाग में है। शासन ने उन्हें तय समय के लिए

प्रतिनियुक्ति दी है। लेकिन, राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को दुरुपयोग कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश जारी किया है और उन्हें एक एक तरफा कार्यभार भी कर दिया है। इस मामले को सुनवाई जस्टिस एफ प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई, उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्यभार करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था करने को कहा है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह एक सामान्य वायरस है, जिससे घबराहना नहीं है। इस वायरस से इन्फेक्शन होने में पहले भी लक्षण नहीं होते थे। साथ ही विशेष लेब शुरू करने की तैयारी है, जिसमें संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर अन्य टेस्ट होंगे।

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रशासन को इन्फ्यूएन्जा और गंधीर तीव्र क्षयन के संबंधित रोगियों की निगरानी रखने को कहा है। बाहरी



उत्सव हाथ कुछ नहीं आया ऐसे में शासन-प्रशासन से मांग की गई। पूर्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस द्वारा जारी की घोषणा पर चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को

2 सौ से अधिक चिटफंड कंपनियों ने 1.59 लाख निवेशकों से ठगे 423 करोड़

धर्मपुरी, 8 जनवरी (हाईवे चैनल)। जिले में लाखों निवेशकों के खून परतने की कमाई सातों चिटफंड कंपनियों में फंसी हुई है। जिसके मिलने के इंतजार में निवेशक हैं लेकिन सातों बीतने के बाद मात्र कुछ लोगों को ही कुछ राशि मिल पाई शेष अधिकांश निवेशकों का ईंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है।

ज्ञात हो कि जिले सहित प्रदेश भर में चिटफंड कंपनियों ने भीली भाली जनता को रकम जमा करवा कर कई लुभावने स्कीम बताते साथ ही एजेंट के तौर पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया। जिससे स्कीम पर लोगों का भरोसा बढ बढ़ गया। यह प्रक्रिया सातों तक जारी रहा। शुरूआत के कुछ सालों में जिनका मैथ्यूरीटी टाइम पूरा हुआ उन्हें स्कीम के तहत भी दुगुनी-तिगुनी राशि लीडार्ड गई इससे लोगों का भरोसा और बढ गया और लोग बढ चढ़कर स्कीम में पैसा लगाने लगे लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों की मेहनत की कमाई को चिटफंड कंपनी बंदी कर नौ दो ग्यारह



उत्सव हाथ कुछ नहीं आया ऐसे में शासन-प्रशासन से मांग की गई। पूर्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस द्वारा जारी की घोषणा पर चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को

हो गये। रातोरात कंपनियों के दबतर गायब हो गये अधिकांश कर्मचारी नजर नहीं आये इसके बाद ठगी का खुलासा हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। कंपनियाँ कैसे लेकर फरार हो गईं।

बता दें कि जिले के लगभग 1.59 लाख निवेशकों से 200 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने 423 करोड़ की ठगी की। इसके बाद लोग एजेंटों के पीछे लगे रहे लेकिन उनसे हाथ कुछ नहीं आया ऐसे में शासन-प्रशासन से मांग की गई। पूर्व में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस द्वारा जारी की घोषणा पर चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम को

प्राथमिकता के साथ वापस दिलाने का वादा किया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार सरकार का कार्यकाल बीत गया इसके बाद भी रकम नहीं मिली। इसके बाद साथ सरकार को सत्ता में आए एक साल से ज्यादा हो गई है लेकिन अब तक निवेशकों के रकम वापस की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हुए।

कोर्ट में लंबित मामलों व अन्य प्रक्रियाओं से लटका मामला

ठगी के बाद कई मामले चिटफंड कंपनियों और उनके अधिकारियों पर अपराध दर्ज हुआ। जिसके चलते कोर्ट द्वारा कंपनियों के संपत्ति को जप कर लिया गया। मामला विचारणीय होने के कारण संपत्ति बेवकाल भी रकम नहीं लौटाई जा सकी। साथ ही सेवा सशित अन्य संस्थाओं द्वारा कंपनी के एकाउंट से वित्तीय लेवने पर भी रोक लगाई गई। ऐसे कई कानूनी प्रक्रियाओं से भी रकम वापसी में देरी हुई। हालांकि कुछ लोकल कंपनियों जिन्हें ठगी स्थानीय व प्रदेश भर ज्यादा हो चुकी है जो कि ऊंच के मुह में खोरे के समान साबित हुई। अभी भी जिले के निवेशकों के 4 अरब से ज्यादा की राशि कंपनियों में फंसी हुई है।

सनावल को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर तेजी से चल रहा पुल का काम

रावपुर, 8 जनवरी (हाईवे चैनल)। बलरामपुर-रामनृजंग जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों को करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग राजना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बाहरी महंगे निवांभ आवागमन की सुविधा मिलेगी।



लोक निर्माण विभाग द्वारा बलरामपुर-रामनृजंग जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के भीली और झारखंड के गढ़वा जिला के धुकी प्रखंड के बालचीर के बीच कन्हर नदी पर 15 करोड़ 20 लाख रूप के लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। अभी 12 पियर एवं दो अवरटेमेंट में से पांच पियर एवं एक अवरटेमेंट का काम पूर्ण कर लिया गया है। शेष सात पियर एवं एक अवरटेमेंट में सस-स्ट्रकर का कार्य प्रगति पर है। अगले कुछ दिनों में सस-स्ट्रकर का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 312 मीटर लंबाई और 8.4 मीटर चौड़ाई के इस पुल का करीब 50 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्माण में पूर्ण गतिवा सुनिश्चित करते हुए समय-समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा पुल का काम अगले साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कन्हर नदी पर छत्तीसगढ़ के भीली और झारखंड के बालचीर गांव के बीच पुल के निर्माण से बालरामपुर-रामनृजंग तहसील के अनेक गांव सोंधे झारखंड से जुड़ जाएंगे। इससे क्षेत्र में व्यापारिक-व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही खरीदारी, इलाज और विभिन्न कार